



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]

नई दिल्ली, दृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2003/अग्रहायण 13, 1925

No. 198]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2003/AGRAHAYANA 13, 1925

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2003
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 1-सी.ए.(7)/64ए/2003.—चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में फिर से संशोधन करने के लिए कुछ प्रारूप-संशोधन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की अधिसूचना सं. 1-सी.ए. (7) 164/2002, दिनांक 24 सितंबर, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-III, धारा 4, दिनांक 5 अक्टूबर, 2002 में पृष्ठ 4396 से 4407 पर प्रकाशित किए गए थे;

और चूंकि उपरोक्त राजपत्र के प्रतियों के जन साधारण के लिए मुद्रित किए जाने के 45 दिन के अंदर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और चूंकि उपरोक्त राजपत्र 9 अक्टूबर, 2002 को जन साधारण के लिए उपलब्ध करा दिया गया था;

और चूंकि संशोधन—प्रारूपों पर जन साधारण से आक्षेप और सुझावों पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा विचार कर लिया गया है और केन्द्रीय सरकार ने इसे अनुमोदित कर दिया है;

अतः, अब, उपरोक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद्, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, इसके द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.—(1) विनियम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2003 कहे जा सकेंगे।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में—

(i) विनियम 204 में “अनुसूची” “ग”, “घ”, “ड”, “च” और “छ” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर “अनुसूची” “ग”, “घ”, “ड”, “च”, “छ” और “ज” शब्द और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

“अनुसूची ज”

(अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में स्मातकोत्तर पाठ्यक्रम)

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में डिप्लोमा कोर्स

(1) उद्देश्य

इस कोर्स का उद्देश्य अभ्यर्थियों को निम्नलिखित क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान प्रदान करना तथा सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.टी.सी. से संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र का व्यावहारिक विकास के लिए विशिष्ट ज्ञान देना भी है।

— अनुसूची व्यापार विधियां

- डम्पिंग रोधी
- एंटी सब्सीडी
- प्रतिस्पर्धी विधियाँ
- ट्रिप्स और ट्रिम्स
- गेट करार
- गेट्स करार

(2) इस व्यापार विधि और डब्ल्यूटी. कोर्स में,—

— भाग 1—सैद्धांतिक ज्ञान और परीक्षा

— भाग 2—व्यावहारिक प्रशिक्षण और डिस्परेशन का जमा किया जाना।
कोर्स के लिए पास भाग-1 को पूर्ण करने के पश्चात् भाग-2 के लिए रजिस्ट्रेशन कराएगा।

कोर्स पूर्ण करने वालों को अनुमोदित प्रारूप में एक प्रमाणपत्र प्रदत्त किया जाएगा और वे अपने नाम के साथ “DITL (ICAI)” अक्षर लिखने के लिए प्राधिकृत होंगे।

भाग 1—सैद्धांतिक ज्ञान और परीक्षा

2. प्रशासन और परीक्षा में प्रवेश

इन विनियमों के विनियम 176 में किसी बात के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटी.ओ. कोर्स, परिषद् द्वारा नियुक्त व्यापार विधि और डब्ल्यूटी.ओ. की समिति (जिसे इस अनुसूची में “समिति” कहा गया है) के अधीन होगा। इस संबंध में समिति के कृत्य, अन्य बातों के साथ-साथ, परीक्षा कराने, उसमें प्रवेश, परीक्षाओं की नियुक्ति और चयन परिणामों की घोषणा और अन्य संबंधित विषय।

कोई भी अभ्यर्थी, व्यापारिक विधि और डब्ल्यूटी.ओ. कोर्स के भाग-1 में तभी प्रवेश पा सकेगा जबकि वह परीक्षा के समय सदस्य हो।

3. रजिस्ट्रीकरण और शिक्षण शुल्क

कोर्स के भाग-1 का रजिस्ट्रीकरण और शिक्षण शुल्क रुपए 20,000 होगा (जिसमें शिक्षण की सामग्री भी होगी)। समिति शिक्षण से संबद्ध एक समुचित सूची और शिक्षण की सामग्री अभ्यर्थियों के लिए तैयार करेगी।

4. परीक्षाओं का संचालन

(1) परीक्षाएं उस अवधि में, उस रीति में और उस समय तथा स्थान पर होंगी जैसा परिषद् निर्दिष्ट करे।

(2) परीक्षा की तिथियाँ और स्थान तथा अन्य विशिष्टियाँ राजपत्र में अधिसूचित की जाएंगी।

(3) परीक्षा में प्रवेशार्थी अभ्यर्थी को ऐसी फीस, जो कि प्रत्येक ग्रुप के लिए दस हजार रुपए से अधिक होगी या अन्य राशि, जो कि परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, देनी होगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार, ग्रुप “ए”, ग्रुप “बी” या दोनों ग्रुपों की परीक्षाएं दे सकेंगे।

(4) व्यापार विधि और डब्ल्यूटी.ओ., भाग-1 परीक्षा का अभ्यर्थी सामान्यतः पास घोषित किया जा सकेगा, यदि वह एक ही बार में दोनों ग्रुपों की या एक बार में एक ग्रुप और बाकी ग्रुपों की पश्चात्वर्ती परीक्षा और कुल 50 प्रतिशत अंक ग्रुप के प्रत्येक पेपरों में मिलाकर प्राप्त किए हों।

5. परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र

परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र, अनुमोदित फार्म में, जिसकी एक प्रति समिति के सचिव से प्राप्त की जा सकेगी, और विनिर्दिष्ट फीस के साथ, इस प्रकार प्रेषित की जा सकेगी कि यह दिए गए नियमों के अनुरूप परिषद् को प्राप्त हो जाए।

6. परीक्षा फीस का लौटाया जाना

(1) किसी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी द्वारा देय फीस, उप पैरा (3) के अधीन देय होगी अन्यथा नहीं।

(2) यदि अभ्यर्थी परिषद से फीस अगली परीक्षा के लिए इस आधार पर अंतरित करने की प्रार्थना करता है कि वह अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका था, तो, परिषद् उस अभ्यर्थी द्वारा दी गई फीस, अगली ली जाने वाली परीक्षा तक, समायोजित करने की अनुमति दे सकेगी।

परंतु परीक्षा समाप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के पश्चात् प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. अनुचित ढंग अपनाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्रक्रिया -

यदि समिति को यह सूचना दी जाती है कि अभ्यर्थी ने परीक्षा पास करने के लिए अनुचित ढंग अपनाया है या उसका प्रयत्न किया है तो समिति इसकी जांच करेगी और परिषद को एक रिपोर्ट देगी, जो कि अगली जांच, यदि आवश्यक समझे तो, करने के पश्चात् अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

परन्तु अभ्यर्थी को उसके विरुद्ध आदेश पारित किए जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

8. परीक्षक

समिति ऐसे प्रबंध और ऐसे परीक्षकों को नियुक्त, के लिए, जो कि प्रश्न पत्र तैयार करेंगे तथा उत्तर पुस्तकाओं का मूल्यांकन करेंगे, जैसा वह ठीक समझे, कर सकेगी।

9. परिणामों का संशोधन

यदि किसी मामले में यह प्रतीत होता है कि उसमें किसी गलती, अनुचित कार्य, धोखा देकर, अनुचित व्यवहार या अन्यथा परीक्षा के परिणामों पर प्रभाव पड़ता है तो समिति को इसमें वर्णित के अतिरिक्त, यह शक्ति होगी कि वह परिणाम को गारंटी के अनुरूप संशोधित करे और ऐसी घोषणा करे, जैसी समिति इस बारे में आवश्यक समझे।

10. कोर्स का भाग-I पर्सनल कॉटेक्ट प्रोग्राम (पी.सी.पी.) द्वारा समर्थित होगा पी.सी.पी. देश के उन केंद्रों उन समयों और स्थानों पर होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। पी.सी.पी. कम से कम 30 दिन की अवधि के होंगे, जिसके लिए अलग से फीस, जो विनिर्दिष्ट की जाए, वसूल की जाएगी।

पर्सनल कॉटेक्ट प्रोग्राम कोर्स के भाग-I के सभी पेपरों के अंतर्विषयों पर आधारित होगा। पर्सनल कॉटेक्ट प्रोग्राम में उपस्थिति का रिकार्ड (कम से कम 80% उपस्थिति का रिकार्ड) परीक्षा में प्रवेश के प्रस्तुत करना होगा।

11. प्रमाणपत्र दिया जाना -

ऐसे अभ्यर्थी को जिसने कोर्स के भाग-I की परीक्षा पूरी कर ली है, विहित प्रारूप में एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

12. पेपरों का विवरण और कोर्स की अंतर्वस्तु -

अभ्यर्थी को भाग-I के निम्नलिखित पेपरों में बैठना होगा -

ग्रुप ए

पेपर I : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रस्तावना

पेपर II : गैट, मूल के नियम और व्यापार संबंधी

करार

पेपर III : गेट, ट्रिप्स और ट्रिम्स डब्ल्यू.टी.ओ. में पुनर्विलोकन की प्रक्रिया।

एस.पी.एस. और विवाद सुलद और

ग्रुप बी

पेपर IV : घरेलु व्यापार विधि

प्रति V : डंपिंग विरोधी, सब्सिडी विरोधी और

संरक्षण -

विधियां और व्यवहार

प्रति VI : प्रतिस्पर्धा विधियां तथा नीतियां

प्रति VII : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुल : 100 अंकप्रस्तावना

ग्रुप ए

प्रति I : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मूल तत्त्व

प्रति II : विश्व व्यापार संगठन की संरचना और कार्यकरण

प्रति III : विश्व व्यापार संगठन की संरचना और कार्यकरण

प्रति IV : मित्र राष्ट्रों की संघी

प्रति V : विशिष्ट और अन्यथा व्यवहार

प्रति VI : विशिष्ट और अन्यथा व्यवहार

प्रति VII : टैरीफ और नान-टैरीफ बेरियर्स

पेपर II गेट, मूल के नियम और व्यापार (100 अंक)

संबंधी करार

पाठ्यक्रम

1. मूल के नियमों संबंधी करार

2. लदान पूर्व निरीक्षण के करार

3. आयात लाइसेंस प्रक्रिया संबंधी करार

4. वस्त्र और कपड़ा संबंध करार

5. कृषि संबंधी करार

6. गेट - 1994 के अन्योदय VII के कार्यान्वयन,

संबंधी करार

7. ऐसे मामलों में निर्णय जहां सीमा शुल्क प्रशासन

को घोषित कीमत की सच्चाई पर संदेह है।

8. व्यापार के तकनीकी बेरियर्स संबंधी करार

9. संबंधित समझबूझ

10. क्षेत्रीय व्यापार करार

11. बहुपक्षीय व्यापार पद्धति के नए मुद्दे और अव्यापारिक मुद्दे

प्रति VIII, ट्रिप्स, ट्रिम, विश्व व्यापार संगठन में पुनर्विनोक्त प्रक्रिया (100 अंक)

• एस.पी.एस. और विवादों में सुलह और

पाठ्यक्रम

1. व्यापारों में व्यापार संबंधी साधारण करार

(;) वित्तीय सेवाओं पर निर्णय

- (ii) नेचुरल परसन्स के मूवमेंट पर परक्रान्ति संबंधी कशर
- (III) वृत्तिक सेवाओं पर निर्णय
2. बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों की व्यापार संबंधी धारणा पर कशर
3. सेनेटरी और फाइटो-सेनेटरी उपयोगों संबंधी कशर
4. विश्व व्यापार संगठन में विवाद सुलझाने की रीति, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम
5. विश्व व्यापार संघठन में पुनर्विलोकन प्रक्रिया - करार, मंत्रियों की बैठकें, उपधरणा प्रक्रिया और एमर्जिंग सीनेसियों ।

ग्रुप बी

पेपर IV : आंतरिक व्यापार विधियां (100 अंक)

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
2. प्रतिल्प्याधिकार अधिनियम, 1957
3. आर्थिक अपराध अधिनियम, 1974
4. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
5. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
6. आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981
7. पेटेंट अधिनियम, 2000
8. विक्रय संवर्धन अधिनियम, 1976
9. व्यापार और वाणिज्यिक चिन्ह अधिनियम, 1958
10. निर्यात-आयात नीति और प्रक्रिया

पेपर V : एंटी डंपिंग, सब्सिडी विरोधी और सुरक्षा - विधियां और प्रचलन(100 अंक)

पाठ्यक्रम

1. एंटी डंपिंग, सब्सिडी और प्रतिरोधी उपायों संबंधी विधियां
2. एंटी डंपिंग उपायों को लागू करना
3. एंटी डंपिंग - विधि और प्रचलन
 - (i) मुख्य उपबंध
 - (ii) डंपिंग की उपधारणा
 - (iii) कीमतों की तुलना
 - (iv) निर्धारित कीमत
 - (v) घरेलू औद्योगिक हानि
 - (vi) आयात की मात्रा
 - (vii) अन्वेषण की प्रक्रिया
 - (viii) उपायों की अवधि
 - (ix) सरकामवेशन कार्रवाई

4. सब्सिडी - विधि और प्रचलन

- (i) एस.सी.एम. संरचना
- (ii) सब्सिडी की परिभाषा
- (iii) रेड, एमबर और ग्रीन सब्सिडी
- (iv) घातक प्रिजुडिस
- (v) सब्सिडी के प्रभावों को समाप्त करना - प्रतिरोधी उचूटी

5. सुरक्षा

- (i) सुरक्षा उपाय
- (ii) क्षतिपूर्ति और बदले की कार्रवाई

6. एंटी डंपिंग, एंटी-सब्सिडी और प्रतिरोधी उपायों, जिनमें भारत सरकार के प्राधिकृत प्राधिकरणों की, यूरोपियन कमीशन और विश्व व्यापार संगठन को विवाद सुलझाने संबंधी रिपोर्ट हैं।

पेपर : VI प्रतिस्पर्धी विधियां और नीतियां (100 अंक)

पाठ्यक्रम

- 1. भारत में एमर्जिंग प्रतियोगिता संबंधी विधियां
- 2. यूरोप में प्रतियोगिता संबंधी विधियां और नीतियां
- 3. यूनाइटेड स्टेट्स और नाफ्टा देशों में प्रतियोगिता संबंधी विधियां और नीतियां
- 4. संक्रमण अर्थ व्यवस्थाओं में प्रतियोगिता संबंधी विधियां और नीतियां
- 5. विश्व व्यापार संगठन के नियम और प्रतियोगिता नीति।

13. पाठ्यक्रम में परिवर्तन आदि -

व्यापार विधि संबंध समिति और विश्व व्यापार संगठन समय-समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन आदि करने के लिए प्राधिकृत है, जो कि इस कोर्स के अन्यथियों को सूचित कर दिया जाएगा।

भाग-2 व्यावहारिक प्रशिक्षण और डिजेशन

का जमा किया जाना

14. व्यावहारिक प्रशिक्षण

(1) कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसने भाग 1 की परीक्षा पास कर ली है, अनुमोदित फार्म में, जिसके साथ विहित फीस भी होगी, जो कि लौटाई नहीं जाएगी, समय-समय पर आवेदन करके अपने आपको भाग-2 (व्यावहारिक प्रशिक्षण) के लिए रजिस्टर कर सकेगा।

(2) उपरोक्त सैद्धांतिक ज्ञान की परीक्षा के अतिरक्त, व्यावहारिक प्रशिक्षण पूर्ण होने पर डिजेशन भी लिखनी होगी, जो कि विश्व व्यापार संगठन के विशेष करारों जैसे वस्त्र निर्माण या कृषि या सेनेटरी और फाइटो-सेनेटरी संबंधी उपायों जैसे विषयों पर होगी तथा उसमें संबंधित विश्लेषण, भारतीय संभावनाओं और भारतीय सेवा दाताओं से संबद्ध मामलों सहित, दर्शाया जाएगा।

(3) व्यावहारिक प्रशिक्षण, विशेष अवधि का वास्तविक कार्य प्रशिक्षण वाणिज्यिक या औद्योगिक संगठनों में, जो कि भारत में या भारत के बाहर हो सकेंगे, दिया जाने वाला प्रशिक्षण होगा, जिसमें प्राथमिकतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ-साथ संक्रमण संबंधी निगमों को भी लिया जाएगा। इन संगठनों में मापदंडों का विस्तृत व्यौरे समिति द्वारा तैयार किया जाएगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों के चुनाव पर निर्णय लेते समय अभ्यर्थी के पद और इस प्रशिक्षण के प्राप्त करने पर, विशेष प्रकार के प्रशिक्षण और अनुभव का अपने संगठन में उपयोग कितना करेगा इस बात का ध्यान रखा जाएगा। यह प्रशिक्षण समिति द्वारा निर्दिष्ट सरकारी संगठन, विभाग, निदेशालय या औद्योगिक उपक्रमों में दिया जा सकेगा, जो कि प्रशिक्षण के तरीके और अभ्यर्थी को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान या अन्य संस्थान में जैसा समिति समय-समय पर अनुमोदित करे।

(5) व्यावहारिक प्रशिक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की किसी फर्म तथा ऐसी सलाहकारी भारतीय फर्म और भारत के बाहर की सार्वजनिक अकाउंटेंट्स फर्म द्वारा भी दिया जा सकेगा। इसके लिए फर्म को निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होगी, अर्थात् :-

- | | |
|--|--|
| (i) फर्म के पास संबंधित क्षेत्र में विशिष्ट | कार्य का कर्तव्य भार है ; |
| (ii) वह अभ्यर्थी जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए वहन करने वाले संगठन में व्यावहारिक | आवेदन किया है से विशिष्ट कर्तव्यभार प्रशिक्षण ले रहा है। |

(6) यदि सदस्य भारत के बाहर की किसी सार्वजनिक अकाउंटेंट्स फर्म में व्यावहारिक प्रशिक्षण पाने का इच्छुक है तो उस फर्म का पार्टनर मानता प्राप्त अकाउंटिंग निकाय से संबद्ध होना चाहिए। ऐसे अकाउंटिंग निकाय का व्यापार विधि संबंधी समिति विश्व व्यापार संगठन से अनुमोदन अनिवार्य होगा।

(7) व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु रजिस्ट्रेशन के आवेदन पर निर्णय लेते समय समिति निम्नलिखित बातों पर ध्यान देगी :-

- | | |
|--|---|
| (i) उस प्रकृति का अनुभव, जो कि अभ्यर्थी | संगठन में प्राप्त करेगा; |
| (ii) विशिष्ट प्रकार का अनुभव प्राप्त करने के | लिए संगठन में पर्यावरण और सुविधाएं हैं; |
| (iii) अभ्यर्थी की उन प्रयोगों को जाने और | प्रयोग करने की इच्छा और प्रक्रिया को |
| जानने की इच्छा है ; और | |
| (iv) अभ्यर्थी अपने आपको नए स्थान में हो रहे | विकास के अनुरूप ढालने का इच्छुक है। |

(8) अभ्यर्थी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए व्यावहारिक अनुभव समिति द्वारा अनुमोदित संगठन /प्राधिकरण में लेना चाहता है और वह उन शर्तों को पूरा करता है जो कि इसमें विनिर्दिष्ट हैं तथा उसे समुचित फार्म में प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाएगा।

(9) भाग-2 में अपने रजिस्ट्रेशन के तत्काल बाद अभ्यर्थी अपना व्यावहारिक प्रशिक्षण आरंभ कर सकेगा।

(10) समिति संगठन का वह मान दंड विनिर्दिष्ट करेगी, जिसमें इसके व्यावहारिक प्रशिक्षण को सेवा के लिए मान्यता दी जाएगी।

(11) उप पैरा (8) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के प्रयोजन के लिए उत्तीर्ण करने की अहता धारण करने के लिए आवेदन कम से कम 6 मास पूर्व करना होगा।

(12) प्रशिक्षण का रिकार्ड -

अभ्यर्थी द्वारा लिए जा रहे प्रशिक्षण का विस्तृत रिकार्ड उसके द्वारा ऐसे फार्म में रखा जाएगा जो समिति विशिष्ट रूप से सुझाए। इस विशिष्ट फार्म में रिपोर्ट तिमाही के आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

(13) इस व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी कम से कम तीन ऐसे तीन क्षेत्र का चुनाव करेगा, जिनमें वह व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। इस क्षेत्र की सुझाई गई सूची में प्रकार है :

- (i) डिपिंग रोधी

- (ii) सब्सिडी
- (iii) सुरक्षा उपाय
- (iv) वस्त्र निर्माण और कपड़ा
- (v) कृषि
- (vi) मूल के नियम
- (vii) अंतरराष्ट्रीय डेरी करार
- (viii) विवादों का निपटारा
- (ix) सेवाओं में व्यापार
- (x) ट्रिएस
- (xi) ट्रिम्स
- (xii) एस.पी.एस.

15. डिजेशन

(i) विनिर्दिष्ट अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण कर रहा अभ्यर्थी समिति द्वारा निर्देश दिए जाने पर, समिति से अनुमोदित विषय पर डिजेशन, प्रशिक्षण पूर्ण होने से तीन मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा :

परन्तु समिति अनुचित मामलों को छोड़कर, डिजेशन प्रस्तुत करने की अवधि को तीन मास से अनधिक तक की अवधि तक बढ़ा सकेगी ।

(ii) अभ्यर्थी उपरोक्त पैरा 14 के उप-पैरा (13) में वर्णित क्षेत्रों में से एक में व्यावहारिक प्रशिक्षण की डिजेशन का चुनाव करेगा ।

(iii) अभ्यर्थी समिति से अनुमोदित डिजेशन की प्रति (synopsis) प्रशिक्षण काल में प्राप्त कर सकेगा ।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा उसके मार्ग निर्देशन हेतु शिक्षण कार्य से जुड़े लोगों का पैनल सुझाया जाएगा । इस पैनल में से समिति उसके लिए एक शिक्षक (Academician) और एक वृत्तिक (Pracaititioner) का चयन करेगी ।

(v) डिजेशन के साथ ऐसी फीस दी जाएगी, जो परिषद् समय-समय पर नियत करे, यह फीस वापस नहीं लोटाई जाएगी ।

(vi) अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षण और अनुसंधान के परिणाम की प्रति के साथ डिजेशन की तीन टाइप की गई या मुद्रित प्रतियां प्रस्तुत करेगा ।

(vii) अभ्यर्थी इस आशय का एक कथन भी प्रस्तुत करेगा कि जिस स्रोत से उसने जानकारी ली है वह वास्तव में उसके अपने कार्य से लिए गए हैं तथा यह मूल है और इसमें किसी और व्यक्ति के कार्य को नहीं लिया गया है ।

(viii) समिति अपने द्वारा नियत किए गए रेप्रेसियों को डिजेशन भेजेगी, जो कि यह सलाह देंगे कि डिजेशन समुचित रूप से उच्च कोटि का है इसलिए उसका अनुमोदन किया जाना चाहिए या उसमें संशोधन आपेक्षित है, यदि ऐसा है तो वह किसी तरह से होगा या उसे निरस्त किया जाना चाहिए ।

(ix) यदि अभ्यर्थी उप-पैरा (i) में विनिर्दिष्ट अवधि में या समिति द्वारा बढ़ाई गई अवधि में डिजेशन प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उप-पैरा (i) के अधीन उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा :

परन्तु समिति एक हजार रुपए की विहित फीस के साथ उसको आवेदन किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण कर सकेगी । यह फीस तब ही लोटाई जाएगी जब उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाता और यह अवधि अभ्यर्थी द्वारा किए गए प्रशिक्षण की अवधि में उप पैरा (i) के अनुरूप सममित की जाएगी ।

16 साक्षात्कार -

समिति द्वारा उसके लिए नियुक्त किए गए साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष अभ्यर्थी को उपस्थित होना पड़ेगा।

17 प्रमाणपत्र का दिया जाना -

प्रत्येक अभ्यर्थी जिसने व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसकी डिजेर्शन अनुमोदित कर दी गई है और उसे साक्षात्कार बोर्ड ने सफल घोषित किया है, को विहित फार्म में एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

डॉ. अशोक हस्तिया, सचिव

[विज्ञापन-3/4/असाधारण/104/03]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December, 2003
(Chartered Accountants)

No. 1-CA(7)/64A/2003.—Whereas certain draft amendments further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, were published by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), at pages 4396 to 4407 of the Gazette of India, Part III Section 4, dated the 5th October, 2002 under the notification of the Institute of Chartered Accountants of India No. 1-CA(7)/64/2002 dated 24th September, 2002;

And whereas objections and suggestions were invited before the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the said Gazette were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 9th October, 2002;

And whereas the objection and suggestion received from the public on the said draft amendments had been considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India and approved by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the said Act, the Council, with the approval of the Central Government, hereby, makes the following amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Second Amendment) Regulations, 2003.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.
2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988, -
 (i) in regulation 204, for the words and letters "Schedules 'C', 'D', 'E', 'F' and 'G'", the words and letters "Schedules 'C', 'D', 'E', 'F', 'G' and 'H'" shall be substituted;

(2) The dates and places of the examination and other particulars shall be notified in the official Gazette.

(3) A candidate for admission to the examination shall pay such fee, not exceeding Rupees One Thousand for each group or any other sum as may be fixed by the Council from time to time. Candidates can appear either for Group A or Group B or for both Groups at their discretion.

(4) A candidate for the Trade Laws and WTO Part I examination shall ordinarily be declared to have passed the examination if he/she passes in both the groups simultaneously or in one group at one examination and in the remaining group at any subsequent examination, securing at one sitting a minimum of 40 per cent marks in each paper of the Group and a minimum of 50 per cent marks of the total marks of all the papers in that Group.

5. Application for admission to examination. - An application for admission to the examination shall be made in the approved form, a copy of which may be obtained from the Secretary of the Committee and together with the specified fee, shall be sent so as to reach the Council in accordance with the directions given by it.

6. Refund of Examination Fee. - (1) The fee paid by a candidate who has been admitted to an examination shall not, except as otherwise provided in subparagraph (2) be refunded.

(2) Where a candidate applies to the Council for the transfer of fee to the next examination on the ground that he was prevented from attending the examination on account of circumstances beyond his control, the Council may permit the fee paid by such candidate to be adjusted toward the fee payable only for the next following examination:

Provided that no such application received after the expiry of fifteen days of the last date of the examination shall be considered.

7. Action against candidates resorting to unfair means. - If it is reported to the Committee that a candidate has resorted to or has attempted to resort to unfair means for the purpose of passing the examination, the Committee shall hold an enquiry and submit a report to the Council which may, after any further investigation as it may consider necessary, take such disciplinary action against the candidate as it thinks fit:

Provided that an opportunity shall be given to the candidate of being heard before an order adverse to him is passed.

8. Examiners. - The Committee may make such arrangements and may appoint such examiners to set question papers and evaluate answer books, as it may deem fit.

9. Amendment of Result. - In any case where it is found that the result of an examination has been affected by error, malpractice, fraud, improper conduct or other matter of whatever nature, the Committee hereinbefore mentioned shall have the power to amend such result in such manner as shall be in accordance with the

"SCHEDULE H
(POST QUALIFICATION COURSE IN INTERNATIONAL TRADE LAWS
AND WORLD TRADE ORGANISATION)

1. Course for Diploma in International Trade Laws and World Trade Organisation. – (1) **Objective.** – The objective of this course is to provide the candidates with a thorough knowledge of the following areas and to equip members with the specialised skills necessary for developing a dedicated practice in the area of services related to International Trade Laws and WTO

- Domestic Trade Laws
- Anti-dumping
- Anti-subsidy
- Competition Laws
- TRIPS and TRIMs
- GATT Agreements
- GATS Agreement

(2) This Trade Laws and WTO Course shall include:-

- **Part I** - Theoretical knowledge with examination
- **Part II** - Practical Training and submission of a dissertation

A member eligible for the course has to complete Part I first before registering for Part II of the Course.

A certificate in the approved form shall be granted to those who qualify in the Course and they shall be entitled to use the letters "DITL (ICAI)" after their names.

Part I - Theoretical knowledge with examination

2. Administration and admission to the examination. – Notwithstanding anything contained in Regulation 176 of these Regulations, the International Trade Laws and WTO Course shall be under the charge of the Committee on Trade Laws and WTO appointed by the Council for the purpose (referred in this Schedule as the "Committee"). The Committee's functions, in this regard, shall, *inter alia*, include holding of examination, admission thereto, appointment and selection of examiners, prescription of books for the guidance of candidates, declaration of results and other allied matters.

No candidate shall be admitted to the Part I Examination of the Trade Laws and WTO Course unless he is a member at the time of appearing at the examination.

3. Registration And Tuition fee. – Registration and tuition fee for the Part I of the course shall be Rs. 20,000/- including the cost of study material. The Committee shall provide an appropriate list of study materials as well as prepared study material to the candidates.

4. Conduct of examinations. – (1) The examination may be conducted at such interval, in such manner and at such time and places, as the Council may direct.

true position and to make such declaration as the Committee shall consider necessary in that behalf.

10. Part I of the course will be supported by Personal Contact Programmes (PCPs). PCPs are to be held at such centres in the country, at such times and places as may be specified. These PCPs will be for a minimum duration of 30 days for which a separate fee shall be charged as may be specified.

The personal contact programme will cover the subject matter of all the papers contained in Part I of the Course. The record of attendance in the personal contact programme (with a minimum attendance record of 80%) must be produced at the time of applying for admission to the examination.

11. Grant of Certificate. - A candidate who has completed the Part I Examination of the course shall be awarded for a Certificate in the appropriate form.

12. Details of Papers and Course Contents. - The candidate shall have to appear for the following papers for Part I

Group A

- Paper I: Introduction to International Trade
Paper II: GATT, Rules of Origin and Trade Related Agreements
Paper III: GATS, TRIPS and TRIMs, SPS and Dispute settlement and review procedures in WTO

Group B

- Paper IV: Domestic Trade Laws
Paper V: Anti-dumping, anti-subsidy and Safeguards – Laws and Practice
Paper VI: Competition Laws and Policies

Detailed Course Contents:

Group A

Paper I Introduction to International Trade (100 marks)

Syllabus

1. Fundamentals of International Trade
2. GATT, 1947
3. GATT 1994 (Marrakesh Agreement)
4. Agreement establishing the World Trade Organisation
5. Structure and working of the WTO
6. Most Favoured Nations Treatment
7. Special and differential treatment
8. Tariffs and non-tariff barriers

Paper II GATT, Rules of Origin and Trade Related Agreements (100 marks)

Syllabus

1. Agreement on Rules of origin
2. Agreement on Pre-shipment inspection
3. Agreement on Import Licensing Procedures
4. Agreement on Textiles and Clothing
5. Agreement on Agriculture
6. Agreement on Implementation of Article VII of GATT, 1994
7. Decisions regarding cases where customs administration have reasons to doubt the truth or accuracy of the declared value.
8. Agreement on Technical Barriers to trade
9. Relevant Understandings
10. Regional Trading Agreements
11. New Issues and Non-trade issues in Multilateral trading system

Paper III GATS, TRIPS, TRIMs, SPS and Dispute Settlement and Review Procedures in WTO (100 marks)

Syllabus

1. General Agreement on trade in services
 - (i) Decision on financial services
 - (ii) Decision on negotiations on movement of natural persons
 - (iii) Decisions on Professional Services
2. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
3. Agreement on the Application of Sanitary and Phyto-sanitary measures
4. Dispute settlement mechanism under WTO, International commercial arbitration
5. Review procedures of WTO – Agreements, ministerial meetings, evolution process and emerging scenario

Group B

Paper IV Domestic Trade Laws (100 marks)

Syllabus

1. Consumer Protection Act, 1986
2. Copyright Act, 1957
3. Economic Offences Act, 1974
4. Environment Protection Act, 1986
5. Essential Commodities Act, 1955
6. Essential Commodities(special provisions) Act, 1981
7. Patents Act, 2000
8. Sales Promotions Act, 1976
9. Trade and Merchandise Marks Act, 1958
10. Export import policy and procedure

Paper V Anti-dumping, Anti-subsidy and Safeguard - Laws and Practices (100 marks)

Syllabus

1. Agreement on anti-dumping, subsidies and countervailing measures
 2. The application of anti-dumping measures
 3. Anti-dumping – Law and Practice
 - (i) Main provisions
 - (ii) Dumping determination
 - (iii) Price comparisons
 - (iv) Constructed price
 - (v) Domestic industry injury
 - (vi) Volume of import
 - (vii) Procedures for investigation
 - (viii) Duration of measures
 - (ix) Circumvention action
 4. Anti-subsidy – Law and Practice
 - (i) Structure of SCM
 - (ii) Definition of subsidies
 - (iii) Red, Amber and Green Subsidies
 - (iv) Serious prejudice
 - (v) Extinguishing the effect of subsidy – the Countervailing duty
 5. Safeguards
 - (i) Safeguard measures
 - (ii) Compensation and retaliation
 6. Case Laws on Anti-Dumping, Anti-subsidy and countervailing measures including reports of the Designated Authority of Government of India, European Commission and of the WTO dispute settlement machinery

Syllabus

1. Emerging Competition Laws in India
 2. Competition Law and policies in the European Union
 3. Competition Law and policies in the United States, NAFTA Countries
 4. Competition Law and policies in the transition economies
 5. WTO Rules & Competition Policy

13. Updation/Revision of the Syllabus. - The Committee on Trade Laws and I.T.O is authorised to update/ revise the syllabus, from time to time, which will be intimated to the candidates, enrolled for the course.

Part II - Practical Training and submission of a dissertation

14. Practical Training. - (1) A candidate can register himself for Part II (Practical Training) after qualifying in the Part I examination of the Course by

submitting an application in the approved form with such fee as may be fixed by the Council from time to time, which shall not be refunded.

(2) In addition to theoretical knowledge with examination as detailed above, the candidate will also have to write a dissertation, after undergoing practical training, on a specific WTO agreement such as Textiles or Agriculture or Sanitary and Phyto-Sanitary measures etc., with relevant analysis, with supporting case laws highlighting the opportunities for India and Indian Service Providers.

(3) Practical training is on the job training for the specified period which shall be undergone with commercial or industrial organisations, both within and outside India, which are primarily involved in international trade as well as transnational corporations. The details of the criteria for the organisations in this regard will be specified by the Committee.

(4) In deciding applications for registration, weightage will be given to the position held by the candidate and the opportunities available to him for receiving the requisite type of training and experience in the organisation. The training may also be undergone in any Government organisation, department, directorate or industrial undertaking as may be specified by the Committee, depending upon the type of the undertaking as well as involvement of the candidate in any research project conducted by the Institute of Chartered Accountants of India or by other Institutions as may be approved by the Committee from time to time.

(5) Practical training may also be undergone in professional firms of Chartered Accountants and other consultancy firms in India and in firms of Public Accountants outside India. For this purpose, firms satisfying the following requirement may be considered suitable:

- (i) The firm is having adequate assignment in the concerned area of specialisation.
- (ii) The candidate applying for registration of practical training is working on the assignments in that area of specialisation.

(6) If a member desires to undergo practical training with a firm of Public Accountants situated outside India, the partners of such firm should belong to a recognised accounting body. Such an accounting body will have to be approved by the Committee on Trade Laws and WTO.

(7) Considerations taken into account by the Committee in deciding application for registration of practical training include:

- (i) The type of experience that the candidate would be getting in the organisation;
- (ii) The environment in the organisation and the facilities available for getting requisite experience;
- (iii) The candidate's desire to learn and urge to go beyond the formalised procedure and seek out the rationale behind methods and procedures; and

- (iv) The candidate's inclination to keep himself abreast of the developments taking place around him.
- (8) A candidate shall undergo practical training for a specified period in the organisations / authorities that may be recommended by the Committee in this behalf and who satisfies the conditions hereinafter mentioned, shall be granted a certificate in appropriate form.
- (9) A candidate may begin his practical training immediately after registration for this Part II.
- (10) The Committee may specify the criteria for organisations, service in which may be recognised towards practical training referred to hereinbefore.
- (11) A candidate desiring to qualify himself for the grant of a certificate referred to in sub-paragraph (8) shall make an application, at least six months in advance giving notice of his intention to qualify for the same.
- (12) Record of training. -

A complete record showing the details of training undergone by the candidate shall be maintained by him in the specified formats to be suggested by the Committee. Report in the specified format shall be submitted to the Committee on a quarterly basis.

(13) During this practical training the candidate shall choose a minimum of three areas in which he shall do detailed practical work. A suggested list of areas is given below:

- (i) Anti-dumping
- (ii) Anti subsidies
- (iii) Safeguards
- (iv) Textiles & Clothing
- (v) Agriculture
- (vi) Rules of origin
- (vii) International Dairy Agreement
- (viii) Disputes Settlement
- (ix) Trade-in-services
- (x) TRIPS
- (xi) TRIMs
- (xii) SPS

15. Dissertation. - (i) A candidate, after undergoing the practical training for a specified period, as may be directed by the Committee, shall submit a dissertation

on a subject to be approved by the Committee, within a period of three months from the date of completion of training:

Provided that the Committee in appropriate cases may extend the time for submission of the dissertation for a period not exceeding three months.

(ii) Candidate shall choose any one of the areas as listed under practical training for his dissertation as mentioned in sub-para (13) of para 14 above.

(iii) The Candidate has to get the synopsis of the dissertation approved by the Committee during the period of training.

(iv) The candidate shall suggest a panel of guides for himself consisting of academicians and practitioners. The Committee shall choose from that panel one academician and a practitioner to act as guides for the candidates.

(v) The dissertation shall be submitted with such fee as may be fixed by the Council from time to time, which shall not be refundable.

(vi) The candidate shall submit in English three typewritten or printed copies of the dissertation embodying the results of his training and research.

(vii) The candidate shall further submit a statement indicating the sources from which his information has been derived and the extent to which he has based his work on the work of others and shall indicate which portion or portions of his work he claims as original.

(viii) The Committee shall forward the dissertation to the referees appointed by it for their advice whether the dissertation is of a sufficiently high degree of merit as to deserve approval or whether it may be modified and if so, in what manner, or whether it may be rejected.

(ix) If a candidate fails to submit the dissertation within the period as specified in sub-paragraph(i) above or such extended period as the Committee may grant under the proviso to the said sub-paragraph (i), his registration for practical training shall stand cancelled:

Provided that the Committee may renew the registration at its discretion, on receipt of an application from the candidate together with a fee of one thousand rupees, which shall not be refunded except where the application is not entertained and on such renewal the period of training already undergone by the candidate shall be counted towards practical training as referred to in sub-paragraph (i) above.

16. Interview. - The candidate shall be required to appear before an interview board that may be appointed by the Committee in this behalf.

17. Grant of Certificate. - A candidate who has completed the practical training, whose dissertation has been approved and who has been successful at the interview, shall be awarded a Certificate in the approved form."

Dr. ASHOK HALDIA, Secy.
[ADVT-3/4/Extraordinary/104/03]